RE: FAST UNTO DEATH BY STUDENTS WHO GOT THEIR MEDICAL DEGREE FROM RUSSIA

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) **:** मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनके दर्शन हमें बड़ी मुश्किल से होते हैं ।.... (व्यवधान)....

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) **:** सवेरे से बैठा हुआ हैं । ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेंश पचौरी) **:** कौशिक जी क्या है आपका ?...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिल : मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। इनके दर्शन हमें बड़ी मुश्किल से होते है। मैडिकल काऊंसिल के सामने कई लडकें, जो रूस से मैडिक्ल कोर्स पढ़कर आए है, अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग यह है कि नेपाल और बंगालादेश से पास किए हुए लड़को का कोई स्क्रीनिंग टैस्ट नहीं कराया जा रहा है, हम लोगो से स्क्रीनिंग टैस्ट कराया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे । यहां माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, कम से कम इस बात को देखें आज 4 दिन हो गए उन लड़को को आमरण अनशन पर बैठे हुए, उनमें से कुछ की हालत खराब है। मैं माननीय मंत्री जी का , आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ कहें ।

श्री शत्रुध्र सिंन्हा : महोदय, माननीय सदस्य कह रहे है कि मरे दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं। इतने दिन से देख-रेख कर भी इनका दिल नहीं भरा । ये कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर कौशिक : नहीं भरता, नहीं भरता ।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) **:** इस मैंटर को दिखवा लीजिए ।...(**व्यवधान**)..

श्री शत्रुध्र सिंन्हा : सर मैं इस मैंटर को दिखवा रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) **:** वहां पर क्या-क्या हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है। ....(**व्यवधान**)...

उपसभ्साध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) **:** कई डाक्टरर्स के रजिस्ट्रेशन के केसेज हैं और बाकी चीजें हैं दिखवा लीजिए ।....(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप इसको गंभीरता से देखे कि मैडिकल काऊंसिल में क्या हो रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री शत्रुध्र सिंन्हा : ऐसा नही है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है और मैं इस मामले में और भी जानकारी हासिल कर रहा हूं । मरी नीयत अच्छी है, हमने कोशिश की है । लेकिन जितना साधारण मामला आप बता रही है उतना साधारण नहीं है। हमने इस बारे में आज भी मीटिंग की है ।मैं उस पर भी आ रहा हूं, हमारे एजेंडे में जो बिन्दु था उस पर भी बात की है उपसभाध्यक्ष जी, मेरा ख्याल है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह किया गया है और कोर्ट में कमेंटी बनाने की बात कहीं गई है ।कमेटी बनाकर हमारी रिकमेंडेशन्स वहां गई है, उन रिकमेंडेशन्स के आधार पर इस बात पर जल्छ फैसला होगा । हमारा मंत्रालय इस बीच में इतना

इन्वोल्व नही है, फिलहाल मैं जानकारी दे रहा हूं, बाकी बातें आपके सामने चंद रोज में आ जाएंगी ।

SHORT DURATION DISCUSSION

Serious situation arising out of deterioration of finances of the States and unsustainable debt burden of such States

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to raise a discussion under rule 176 on the serious situation arising out of the deterioration of the finances of the States and unsustainable debt burden of such States, leading to severe curtailment on development activities.

When I was going through a particular document, I was surprised to read page 18 of the document -- dealing with the States finances --where it was stated in a box, "In many States, we have engineers, but no funds for construction or maintenance; doctors, but no medicines; teachers, but no school buildings; a large army of Class III and Class IV employees with no productive work; many Class I and Class II Officers, but little funds for travel, telephone or POL and thus no supervision or monitoring; very little capital expenditure and asset creation; little funds for maintenance". I thought it must be a manifesto of some opposition party to have a dig at the ruling party in one of the States. But it is a document published by the Planning Commission. What I have quoted has been stated in the Draft Approach Paper for the Tenth Plan prepared by the Planning Commission and debated and discussed in the NDC. Mr. Vice-Chairman, Sir, perhaps it is enough to indicate the state of finances of the State Governments.

Sir, I am thankful to you and to the Leader of the House for giving me this opportunity to raise a discussion on this subject because, nowadays, in Parliament we devote less and less time on substantive issues on which, an old timer like me feels, the Parliament should concentrate. If I make a comparison, we are skating on a thin layer of ice uhder which there is a bottomless sea. Nobody knows at what point of time it would break and the whole system would collapse. At one point of time, when the State finances were in a difficult situation, we used to look to the Centre and say, "After all, in our federal structure the Central Government is there and they would be in a position to come to the rescue of the States". But what I find over the years is, the financial position of the